

साप्ताहिक

न्यूज क्राइम फाइल

गुल्य- 02 रूपयें

ग्वालियर, भिंड, मुरैना, छतरपुर, सागर, विदिशा, रायसेन, सिवनी, जबलपुर, रीवा, सतना, होशंगाबाद, हरदा एवं इंदौर में प्रसारित।

विजिट के कुछ घंटों बाद ही कर लिया एमओयू

बारसिलोना में सीएम की मुरीद
हुई टेक जायंट कंपनी सबमर

उदय प्रताप सिंह चौहान

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की स्पेन यात्रा के दौरान मध्यप्रदेश सरकार और वैश्विक टेक्नोलॉजी कंपनी सबमर टेक्नोलॉजीस एस.एल. के बीच डिजिटल और तकनीकी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक समझौता हुआ। बारसिलोना में मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम और सबमर के बीच एमओयू संपन्न हुआ। इस समझौते में निवेश, तकनीकी सहयोग और सतत डिजिटल अवसंरचना के विकास पर फोकस किया गया है। यह समझौता केवल एक सरकारी प्रक्रिया नहीं,

बल्कि नेतृत्व, नीति और परिणाम की मिसाल है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा 17 जुलाई की रात को बारसिलोना स्थित सबमर मुख्यालय के भ्रमण के अगले कुछ ही घंटों बाद यह एमओयू साइन होना निवेश के प्रति मध्यप्रदेश सरकार प्रतिबद्धता का सुदृढ़ कदम है।

मजबूत नेतृत्व और स्पष्ट विजन से वैश्विक निवेशकों का विश्वास तेजी से हासिल करने का भी उदाहरण है। इस समझौते के अंतर्गत मध्यप्रदेश में नेक्स्ट जनरेशन के एआई-रेडी डाटा सेंटर की क्षमता को संयुक्त रूप से 1 गीगावाट तक विकसित करने के लिए एक रणनीतिक सहयोग स्थापित किया गया है। यह

समझौता उन्नत लिक्विड-कूलिंग तकनीकों जैसे इमर्शन कूलिंग और डायरेक्ट-टू-चिप समाधानों पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य ऊर्जा खपत, जल उपयोग और पर्यावरणीय प्रभाव को काफी हद तक कम करना है। यह सहयोग डाटा सेंटर संचालन के लिए वैश्विक दक्षता मानकों के अनुरूप है। यह तकनीक पारंपरिक तरीकों की तुलना में 45 प्रतिशत तक ऊर्जा की बचत और 90 प्रतिशत तक जल संरक्षण करती है। सबमर कंपनी निर्माण, अनुसंधान एवं विकास और तकनीकी क्षेत्र में प्रदेश में निवेश करेगी। वहीं मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम इस परियोजना के लिए उपयुक्त

भूमि, आधारभूत संरचना, नीति सहयोग एवं शासकीय औपचारिकताओं का अंतिम रूप देगा। इस साझेदारी का उद्देश्य न केवल डिजिटल क्षेत्र में राज्य की तकनीकी क्षमता को बढ़ाना है, बल्कि कौशल विकास, नवाचार और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को भी प्रोत्साहित करना है। प्रदेश के युवाओं को अत्याधुनिक डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। सबमर, मध्यप्रदेश में डाटा सेंटरों के डिजाइन और स्थापना में नई पीढ़ी के मानकों को स्थापित करने में सहायता करेगा। सबमर तकनीकी सलाहकार के रूप में काम करते हुए लिक्विड कूलिंग, ऊर्जा अनुकूलन और एआई आधारित अवसंरचना विकास के लिए वैश्विक विशेषज्ञता प्रदान करेगा। यह सहयोग मध्यप्रदेश को टिकाऊ, एआई-रेडी डिजिटल केंद्र के रूप में स्थापित करेगा और राज्य को दीर्घकालिक आर्थिक लाभ देगा।

इस समझौते के अवसर पर सांस्कृतिक सौहार्द्र का सुंदर दृश्य देखने को भी मिला, जब सबमर के फाउंडर श्री पोल वाल्स सोलर मध्यप्रदेश हैंडलूम से बनी विशेष टाई पहनकर एमओयू कार्यक्रम में शामिल हुए। यह समझौता प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'डिजिटल इंडिया' और 'मेक इन इंडिया' अभियानों की भावना के अनुरूप है और मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार की तकनीकी उन्नयन तथा वैश्विक निवेश प्रोत्साहन की प्रतिबद्धता को सशक्त रूप से दर्शाता है।

सबमर टेक्नोलॉजीस की स्थापना वर्ष 2015 में बारसिलोना में हुई थी। यह कंपनी डेटा सेंटर, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और एज कंप्यूटिंग के लिए सिंगल फेज इमर्शन कूलिंग प्रणालियों में वैश्विक विशेषज्ञता रखती है। इसके उत्पादों में स्मार्टपॉड, स्मार्टपॉडएक्स, ईएक्सओ और माइक्रोपॉड शामिल हैं। कंपनी ने विश्वभर में वित्तीय संस्थानों, सरकारी क्लस्टर्स और एआई प्रयोगशालाओं में सफलतापूर्वक सिस्टम स्थापित किए हैं। मई 2022 में कंपनी ने भारत में इंग्राम माइक्रो इंडिया के साथ साझेदारी कर देश में स्मार्ट और सस्टेनेबल डाटा सेंटर की स्थापना की।



भोपाल में पैर टच होने पर भड़का; पीड़िता बोली- थाने में बंद करने की दी धमकी

एएसआई ने युवक को पीटा, युवती को मारा मुक्का

न्यूज क्राइम फाइल

भोपाल में बागसेवनिया थाने में पदस्थ एएसआई बृजेश मिश्रा ने एक युवक की पिटाई कर दी। दो युवतियां उसे बचाने पहुंची तो एएसआई ने उन्हें भी धक्का दिया, एक युवती के पेट में मुक्का मारा। घटना शुक्रवार शाम 5 बजे की है। युवक-युवती थाने के सामने कार शोरूम में काम करते हैं। शुक्रवार शाम 5 बजे वे चाय पीने गए थे। इसी दौरान निकलते समय युवक का पैर उनसे टकरा गया था। इससे भड़के एएसआई ने उन्हें पीटा। घटना का वीडियो भी सामने आया है। पीड़ित युवक का आरोप है कि थाने के अंदर भी उसे पीटा। शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देकर छोड़ दिया। पीड़ित युवक और युवती की ओर से सीएम हेल्प लाइन और डीसीपी जोन-2 संजय अग्रवाल के कार्यालय में शिकायत किए जाने की बात कही है।

एएसआई ने चांटा मारा, गालियां दीं

बागसेवनिया थाने के सामने नीरज श्रीवास्तव सेकेंड हैंड कार का शोरूम संचालित करते हैं। इसमें आकाश तिवारी, रितु सिंह परमार और अंजलि मिश्रा सेल्स का काम देखते हैं। तीनों एक साथ शाम को चाय पीने हर रोज की तरह शोरूम के पास गए। यहां एएसआई बृजेश मिश्रा पहले से मौजूद थे। तीनों ने चाय पी और आकाश ने पैसा कटाया। इसके बाद निकलते समय बृजेश से आकाश का पांव टकराया और एएसआई ने उसे चांटा मारकर बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। सरेराह उसे गालियां देने लगा। युवतियों ने बचाने का प्रयास किया तो उनके साथ अभद्रता, झूमाझटकी कर मारपीट कर दी।

पीड़िता बोली- हम मदद की गुहार लगाते रहे

एएसआई वर्दी का रौब दिखाने आकाश को घसीटकर थाने के अंदर ले गया। रितु का आरोप है कि, हम उसे बचाने के लिए पीछे पहुंचे, तब स्टाफ ने हमें अंदर नहीं घुसने दिया। आकाश को बेरहमी से पीटा जा रहा था, यहां एएसआई सहित दो अन्य पुलिसकर्मियों ने उसके साथ मारपीट की। वे चीखता रहा, माफी मांगता रहा लेकिन उसे नहीं छोड़ा गया। हम घबराकर रोने लगे, तब पुलिसकर्मी हम पर हंसते रहे।



धमकी दी- शिकायत की तो करियर खराब कर देंगे

आकाश के मुताबिक, करीब आधे घंटे बाद उसे थाने से छोड़ दिया गया। लेकिन धमकी दी गई कि कहीं भी शिकायत की तो पूरा करियर खत्म कर देंगे। तुम्हारे कर्मों के कारण पूरा परिवार परेशान हो जाएगा। आकाश ने बताया कि शनिवार को पुलिस कमिश्नर कार्यालय में पूरे मामले की शिकायत करेंगे।

टीआई ने कहा- पैर लगने पर कहासुनी

बागसेवनिया थाना टीआई अमित सोनी बोले- पैर लगने की बात पर एएसआई और युवक के बीच कहासुनी हुई थी। बाद में दोनों पक्षों में आपसी समझौता हो गया। इसके बाद युवक थाने से चला गया।

प्रोत्साहन



मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने फिरा दे बार्सिलोना के मोंटजुइक मेला परिसर का भ्रमण कर जानकारी प्राप्त की।

भोपाल में किन्नर बनकर रह रहा था बांग्लादेशी अब्दुल कलाम

न्यूज क्राइम फाइल

भोपाल पुलिस ने शहर के बुधवारा क्षेत्र से बांग्लादेशी नागरिक अब्दुल कलाम को हिरासत में लिया है। वह पहचान बदलकर कई सालों से यहां रह रहा था। लोग उसे नेहा नाम से जानते हैं। इसी नाम से उसने अपना पहचान पत्र भी बनवा रखा है। उसके फर्जी पहचान पत्र को भी कब्जे में ले लिया गया है। पुलिस ने अब्दुल कलाम को सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात में पकड़ा। अभी वह तलैया थाना पुलिस की हिरासत में है। जहां उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह पता लगा रही है कि वह कब से भोपाल में है? क्या वह यहां किसी संदिग्ध गतिविधि में लिप्त रहा है? क्या उसके खिलाफ भोपाल में रहते कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ है? इसके साथ ही उसकी कॉल रिकॉर्डिंग और मोबाइल चैटिंग की भी जांच की जा रही है।



खुफिया एजेंसियां भी जांच में जुटी

खुफिया एजेंसियां भी अब्दुल कलाम के संपर्कों के बारे में जानकारी जुटा रही हैं। पुलिस ने इस मामले को गोपनीय रखने का फैसला लिया है। अब्दुल को भोपाल के तलैया थाने में रखा गया है। जहां, उसे निगरानी में रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। महिला जवान राउंड द क्लॉक उसकी निगरानी कर रही हैं।



कहा- मैंने अवैध खनन का मुद्दा उठाया था; सरकार से मांगी सुरक्षा

भोपाल जिला उपाध्यक्ष बोले- मुझ पर डंपर चढ़वा देंगे माफिया

न्यूज़ क्राइम फाइल

भोपाल जिला पंचायत के उपाध्यक्ष और बीजेपी नेता मोहन सिंह जाट ने सरकार से सिक्योरिटी गार्ड यानी, गनमैन मांगा है। जाट ने बताया, मैंने 11 जुलाई को हुई मीटिंग में भोपाल में अवैध खनन का मुद्दा उठाया था। इसके बाद मुझे खनन माफिया से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। कह रहे हैं कि मुझ पर डंपर चढ़वा देंगे। इसे लेकर उपाध्यक्ष जाट ने कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को लिखित शिकायत भी की है। जिसमें उन्होंने खनिज माफिया, ठेकेदार और बिल्डर्स से सुरक्षा के लिए गनमैन उपलब्ध कराने की बात कही। कलेक्टर सिंह ने बताया, जिला उपाध्यक्ष ने आवेदन दिया है। इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

मुझे खुद आकर धमकियां मिल रही

11 जुलाई को जिला पंचायत में साधारण सभा की बैठक में उपाध्यक्ष जाट ने जिले में बड़े पैमाने पर मुरम का अवैध खनन होने का मुद्दा उठाया था। जिसमें खनिज अधिकारी पर भी नाराजगी जताई थी। इसके बाद कलेक्टर सिंह



ने सभी एसडीएम और खनिज अधिकारी को खदानों के आसपास तार फेंसिंग कराने को कहा था। उपाध्यक्ष जाट ने बताया, कलेक्टर के निर्देश के बाद हुई कार्रवाई के बाद मुझे कुछ लोगों ने जान से मारने की धमकियां दी हैं। पीएचई विभाग के ठेकेदारों ने भी कुछ महीने

पहले अभद्रता की थी। जिला पंचायत में ही राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा द्वारा ली गई बैठक में भी मैंने अवैध कॉलोनियां काटने वाले कॉलोनाइजर्स की शिकायत की थी। इसके बाद कुछ कॉलोनाइजर भी लगातार धमकियां दे रहे हैं। मैंने जो भी मुद्दे उठाए, वे सभी जनहित के

हैं। धमकियां मिलने से जान से खतरा है। इसलिए कलेक्टर को आवेदन देकर गनमैन मांगा है।

जनप्रतिनिधि बोले-हम पौधे रोपे, आप उखाड़ दें, मेरे पास इसके सबूत

भोपाल जिला पंचायत की मीटिंग में उपाध्यक्ष जाट ने खनिज खदानों के आसपास तार फेंसिंग नहीं होने और अवैध खनन का मुद्दा उठाया था। उपाध्यक्ष जाट खनिज विभाग के अफसरों पर जमकर भड़के थे। उन्होंने कहा था कि सरकार पौधे रोप रही है। अभियान चला रही है। हमने भी जंगल और गांवों में पौधे रोपे, लेकिन खनिज खदानों के आसपास से इन्हीं पौधों को उखाड़ दिया गया। मेरे पास इसके सबूत हैं। यदि मैं गलत हूँ तो इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने कहा था कि जिले में बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है। जिम्मेदार अफसरों का इस ओर ध्यान नहीं है। हमने जहां पर पौधे रोपे, उन्हें ही खनिज खदान संचालकों ने जेसीबी से उखड़वाकर फेंक दिया, जबकि खदान की निश्चित सीमा होती है और तार फेंसिंग कराना पड़ती है। पूरे जिले में नियम से ज्यादा खनन हो रहा है। इसमें जिम्मेदार भी शामिल हैं।

उमा भारती बोली- चुनाव के लिए हर वक्त तैयार हूं

राजनीति में शुचिता आई, अब अफसरशाही में आना जरूरी, तभी रुकेगा भ्रष्टाचार

न्यूज़ क्राइम फाइल

पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा है कि राजनीति में अब शुचिता आ चुकी है, लेकिन अफसरशाही में अभी इसकी कमी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को भी राजनीति की तरह शुचिता अपनानी चाहिए, तभी भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। राजधानी भोपाल में मीडिया से चर्चा के दौरान उमा भारती ने यह बातें कही। उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी जिसमें 75 वर्ष की उम्र के बाद सक्रिय राजनीति से दूर रहने की बात कही गई थी। उमा ने स्पष्ट किया कि उनकी उम्र अभी 75 वर्ष नहीं हुई है और इस बयान को लेकर जो भी बातें सामने आ रही हैं, वे पूरी तरह गलत और निराधार हैं।



सरकारी तंत्र से भी झेलनी पड़ी
प्रताड़ना

उमा भारती ने कहा कि 1990 से 1992 के

दौरान जिन सरकारों का दबाव था, उस समय उन्हें प्रताड़ना का सामना करना पड़ा था। उन्होंने यह भी बताया कि 2013 में जब व्यापम

घोटाला उजागर हुआ था, तब भी उनका नाम घसीटा गया और उन्हें उस समय भी मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उन्होंने कहा कि वह अब अपने परिवार से पूरी तरह अलग हो रही हैं, लेकिन राजनीति में सक्रिय बनी रहेंगी। उन्होंने यह भी दोहराया कि गंगा, गोमाता और शराबबंदी को लेकर उनका संघर्ष आजीवन जारी रहेगा।

शराबबंदी पर और प्रयास जरूरी

उमा ने कहा कि केंद्र सरकार गंगा शुद्धिकरण के लिए काम कर रही है और मध्य प्रदेश सरकार ने भी गंगा के संरक्षण के लिए प्रयास शुरू किए हैं। हालांकि, अभी इन दोनों क्षेत्रों में और सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने शराबबंदी के मुद्दे पर भी जोर देते हुए कहा कि इस दिशा में और ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।

स्वच्छता एवं नशामुक्ति के क्षेत्र में अतुलनीय कार्य करते सामाजिक संगठन

इस धरा पर जन्म लेने वाले प्रत्येक जीव के लिए प्रकृति ने पर्याप्त खाद्य पदार्थ दिए हैं परंतु अति लालच के चलते मानव ने प्रकृति का शोषण करना शुरू कर दिया है। इसमें कोई अब कोई संदेह नहीं रह गया है कि मानव ने अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए पर्यावरण का अत्यधिक नुकसान किया है और इसका परिणाम आज उसे ही भुगतना भी पड़ रहा है। कई देशों में तो भयंकर गर्मी में वहां के जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं जिनसे जान और माल की भारी हानि हो रही है। हम पर्यावरण के सम्बंध में बढ़ चढ़ कर चर्चाएं तो करते हैं परंतु आज हमारे गांवों में खेत, प्लांटों में परिवर्तित हो गए हैं। हमारे खेतों पर शोपिंग कॉम्प्लेक्स एवं मॉल खड़े हो गए हैं जिससे हरियाली लगातार कम होती जा रही है। बीते कुछ वर्षों में कंकरीट की इमारतों में अत्यधिक वृद्धि एवं भूमि प्रयोग में बदलाव के चलते भारत में भी तापमान लगातार बढ़ रहा है। देश के महानगर अर्बन हीट आइलैंड बन रहे हैं। अर्बन हीट आइलैंड वह क्षेत्र होता है जहां अगल-बगल के इलाकों से अधिक तापमान रहता है। कई स्थानों पर अत्यधिक गर्मी के पीछे अपर्याप्त हरियाली, अधिक आबादी, घने बसे घर और इंसानी गतिविधियां जैसे गाड़ियों और गैजेट से निकलने वाली हीट आदि कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। कार्बन डाईऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसों एवं कूड़ा जलाने से भी गर्मी बढ़ती है। राजधानी दिल्ली का उदाहरण हमारे सामने है। जहां चारों दिशाओं में बने डंपिंग यार्डों में आग लगी ही रहती है और लोगों का सांस लेना भी अब दूभर हो रहा है। भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो यानी कार्बन उत्सर्जन रहित अर्थव्यवस्था का लक्ष्य तय किया हुआ है। यद्यपि पर्यावरण रक्षा में भारत के प्रयास बहुआयामी रहे हैं लेकिन यह प्रयास तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक देशवासी प्राकृतिक संसाधनों का अनावश्यक अत्यधिक शोषण करना बंद नहीं करते। शहरों के बढ़ते तापमान की रोकथाम हेतु जरूरी है कि मौसम और वायु प्रवाह का ठीक तरह से नियोजन किया जाए। हरियाली का विस्तार, जल स्रोतों की सुरक्षा, वर्षा जल संचय,



वाहनों एवं एयर कंडीशंस की संख्या की कमी से ही हम प्रचंड गर्मी को कम कर सकते हैं। पृथ्वी का तापमान घटेगा तभी मानव सुरक्षित रह पाएगा। उक्त संदर्भ में यह हम सभी भारतीयों के लिए हर्ष का विषय होना चाहिए कि हमारे देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन मौजूद हैं जो सदैव ही सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सेवा कार्य करने वाले संगठनों को साथ लेकर, देश पर आने वाली किसी भी विपत्ति में आगे आकर, सेवा कार्य करना प्रारम्भ कर देते हैं। भारत के पर्यावरण में सुधार लाने की दृष्टि से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तो बाकायदा एक नई पर्यावरण गतिविधि को ही प्रारम्भ कर दिया है। जिसके अंतर्गत समाज में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले संगठनों को साथ लेकर संघ द्वारा देश में प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल नहीं करने का अभियान प्रारम्भ किया गया है और देश में अधिक से अधिक पेड़ लगाने की मुहिम प्रारम्भ की गई है। साथ ही, विभिन्न शहरों को स्वच्छ एवं नशामुक्त बनाने हेतु भी विशेष अभियान प्रारम्भ किए हैं। उदाहरण के तौर पर ग्वालियर को स्वच्छ, नशामुक्त एवं प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने का बीड़ा उठाया गया है। इसी संदर्भ में ग्वालियर

महानगर में विविध संगठनों के दायित्ववान कार्यकर्ताओं का दो दिवसीय शिविर आयोजित किया गया था। इस शिविर के एक विशेष सत्र में इस बात पर विचार किया गया कि ग्वालियर महानगर को स्वच्छ एवं नशामुक्त बनाया जाना चाहिए। उक्त शिविर के समापन के पश्चात उक्त समस्याओं के हल हेतु विविध संगठनों के दायित्ववान कार्यकर्ताओं की तीन बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों में विस्तार से विचार करने के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि कुछ चिन्हित कार्यकर्ताओं को विभिन्न मठ, मंदिरों, स्कूलों, संस्थानों आदि में विषय प्रस्तुत करने हेतु भेजा जाए ताकि उक्त समस्याओं के हल में समाज की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। इस संदर्भ में चुने गए 60 कार्यकर्ताओं के लिए एक वक्ता कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। इन चिन्हित कार्यकर्ताओं को विभिन्न संस्थानों में विषय प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया था ताकि उक्त समस्याओं के हल करने हेतु समाज को भी साथ में लेकर कार्य को सम्पन्न किया जा सके। साथ ही, ग्वालियर को प्रदूषण मुक्त सुंदर नगर बनाए जाने के अभियान को स्थानीय जनता के बीच ले जाने हेतु, माननीय श्री अटल बिहारी

वाजपेयी जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर दिनांक 25 दिसम्बर 2024 को, ग्वालियर के चुने हुए 29 चौराहों पर मानव शृंखलाएं बनाई गई थी, लगभग 8,000 नागरिकों ने इस मानव शृंखला में भागीदारी की थी। इसी प्रकार, ग्वालियर को व्यसन मुक्त नगर बनाए जाने के अभियान को स्थानीय जनता के बीच ले जाने हेतु, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस एवं अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के शुभ अवसर पर, दिनांक 12 जनवरी 2025 को एक विशाल मेराथन दौड़ का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के आयोजन में स्थानीय प्रशासन का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ एवं लगभग 6,000 नागरिकों ने इस मेराथन दौड़ में भाग लिया था। संघ के ग्वालियर विभाग द्वारा ग्वालियर महानगर में अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाने की मुहिम प्रारम्भ की गई। जिसके अंतर्गत ग्वालियर के कई विद्यालयों में वहां के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को साथ लेकर स्वयंसेवकों द्वारा नगर में भारी मात्रा में पौधारोपण किया गया। ग्वालियर की पहाड़ियों पर भी इस मानसून के मौसम के दौरान हजारों की संख्या में नए पौधे रोपे गए हैं। गजराजा स्कूल, केआरजी महाविद्यालय एवं गुप्तेश्वर मंदिर की पहाड़ियों को तो पूर्णतः हरा भरा बना दिया गया है। नगर के प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा नगर के विद्यालयों, महाविद्यालयों, सामाजिक संगठनों, व्यावसायिक संगठनों, धार्मिक संगठनों, एवं नगर के विभिन्न चौराहों पर नागरिकों को शपथ दिलाई जा रही है कि मैं ग्वालियर नगर को प्लास्टिक मुक्त बनाने हेतु, आज से प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल नहीं करूंगा। अभी तक एक लाख से अधिक नागरिकों को यह शपथ दिलाई जा चुकी है। कई स्कूल, कई मंदिर एवं कई महाविद्यालय (लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान - एलएनआईपीई सहित) पोलिथिन मुक्त हो चुके हैं। इसी प्रकार, ट्रिपल आईटीएम प्रबंधन के प्रयास से संस्थान के आसपास दुकानदारों द्वारा मादक पदार्थों के बिक्री करना बंद कर दिया गया है। साथ ही, ग्वालियर महानगर में एक लाख से अधिक नागरिक, नशा नहीं करने का संकल्प ले चुके हैं।

पंच परिवर्तन से बदल जाएगा समाज का चेहरा-मोहरा

इतिहास के चक्र में किसी सांस्कृतिक संगठन के सौ साल की यात्रा साधारण नहीं होती। यह यात्रा बीज से बिरवा और अंततः उसके वटवृक्ष में बदल जाने जैसी है। ऐसे में उस संगठन के भविष्य की यात्रा पर विमर्श होना बहुत स्वाभाविक है। स्वतंत्रता के अमृतकाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संकल्प भविष्य के भारत की रचना में सहयोगी बन सकते हैं। अपने शताब्दी वर्ष में संघ ने 'पंच परिवर्तन' का संकल्प लिया है। यह पंच परिवर्तन क्या है? इससे क्या होने वाला है? इसे भी जानना जरूरी है। संघ की मान्यता है कि व्यवस्था परिवर्तन का लक्ष्य तभी पूरा होगा, जब भारत की व्यवस्थाएं 'स्व' पर आधारित हों। 'स्व' आधारित तंत्र बनाना साधारण नहीं है। महात्मा गांधी से लेकर देश के तमाम विचारक और राजनेता 'स्व' की बात करते रहे, किंतु व्यवस्था ने उनके विचारों को अप्रासंगिक बना दिया। समाज परिवर्तन के बिना व्यवस्था परिवर्तन संभव नहीं, इसे भी सब मानते हैं। वैचारिक संप्रभु इसका बहुत बड़ा कारण है। हम आत्मविस्मृति के शिकार और आत्मदैत्य से घिरे हुए समाज हैं। गुलामी के लंबे कालखंड ने इस दैन्य को बहुत गहरा कर दिया है। इससे हम अपना मार्ग भटक गए। स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, बाबा साहब आंबेडकर हमें वह रास्ता बताते हैं जिनपर चलकर हम अपनी कुरीतियों से मुक्त एक सक्षम, आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी समाज बन सकते थे। किंतु अंग्रेजों के बाद सत्ता में आए नायकों ने सारा कुछ बिसरा दिया। उस आरंभिक समय में भी दीनदयाल उपाध्याय और डा. राममनोहर लोहिया जैसे नायक भारत की आत्मा में झांकने का प्रयास करते रहे किंतु सत्ता की राजनीति को वे विचार अनुकुल नहीं थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने शताब्दी वर्ष में पंच परिवर्तन का जो संकल्प लिया है, वह भारत की चित और उसकी स्मृति को जागृत करने का काम करेगा। राष्ट्रीय चेतना का स्तर बढ़ाने के लिए 1. नागरिक कर्तव्य, 2. स्वदेशी, 3. पर्यावरण संरक्षण, 4. समरसता, 5. कुटुंब प्रबोधन जैसे पांच संकल्प ही पंच परिवर्तन के सूत्र हैं। इन विषयों में भारत की आत्मा को झकझोरकर जगाने और 'नया भारत' बनाने का संकल्प झलकता है। किसी भी राष्ट्र और लोकतंत्र की सफलता उसके नागरिकों की सहभागिता और कर्तव्यबोध से ही सार्थक होती है। एक जीवंत लोकतंत्र की गारंटी उसकी नागरिक चेतना ही है। कानूनों की अधिकता और उसे न मानने का मानस दोनों साथ-साथ चलते हैं। अपनी माटी के प्रति प्रेम, उत्कट राष्ट्रभक्ति ही सफल राष्ट्र का आधार है। जापान जैसे देशों का उदाहरण देते समय हमें देखना होगा कि क्या हमारी राष्ट्रीय चेतना और संवेदना वही है जो एक जापानी में है। आखिर क्या कारण है कि अपनी महान परंपराओं, ज्ञान परंपरा के बाद भी हम एक लापरवाह और कुछ मामलों में अराजक समाज में बदलते जा रहे हैं। कानूनों को तोड़ना यहां फैशन है। यहां तक की हम सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने और सड़कों पर रेड लाइट का उल्लंघन करने से भी बाज नहीं आते। ये बहुत छोटी बातें लगती हैं, किंतु हैं बहुत बड़ी। चुनावों में शत प्रतिशत मताधिकार तो दूर का सपना है। बहुत शिक्षित शहरों में वोटिंग 50 प्रतिशत से आगे नहीं बढ़ पाती।



अवॉर्ड लेकर लौटीं महापौर, एयरपोर्ट पर स्वागत

देश का दूसरा सबसे साफ शहर भोपाल; मेयर-एमआईसी सदस्यों ने एयरपोर्ट पर झाड़ू भी लगाई



न्यूज क्राइम फाइल

स्वच्छ सर्वेक्षण-2024 के नतीजों में भोपाल देश का दूसरा सबसे साफ शहर घोषित किया गया है। गुरुवार को नई दिल्ली में यह खिताब मिला है। महापौर मालती राय और टीम के सदस्य शुक्रवार को दिल्ली से भोपाल लौट आए। इस दौरान सफाई मित्र भी एयरपोर्ट पहुंच गए और महापौर समेत अन्य का स्वागत किया। इसके बाद मेयर और एमआईसी सदस्यों ने एयरपोर्ट पर झाड़ू भी लगाई। महापौर और टीम ने सफाई मित्रों को भी हार पहनाकर मुंह मीठा कराया। महापौर राय, निगम कमिश्नर हरेंद्र नारायण, एमआईसी मंत्री रविंद्र यति, आरके सिंह बघेल, मनोज राठौर, सुषमा बावीसा, पार्षद बृजला सचान सहित भोपाल के दल में शामिल सदस्यों का स्वागत किया गया। महापौर ने स्वच्छता की रैंकिंग में सुधार का श्रेय सफाई मित्रों को देते हुए पुष्प माला से उनका अभिनंदन किया। महापौर, निगम कमिश्नर, पार्षद, निगम अधिकारी-कर्मचारियों ने सफाईकर्मियों का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान ढोल-नगाड़े भी खूब बजे। कई स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी महापौर का स्वागत किया।

12,500 में से 12067 अंक हासिल कर पाया मुकाम

कचरा मुक्त शहरों की श्रेणी में भोपाल को 7 स्टार रैंकिंग भी मिली है। वहीं, भोपाल ने देश की सबसे स्वच्छ तम राजधानी होने के साथ ही वाटर+ सिटी का गौरव भी बरकरार रखा है। रीड्यूज, रियूज, रिसायकल थीम पर हुए स्वच्छ सर्वेक्षण-2024 में भोपाल नगर निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण में निर्धारित 10 हजार अंकों में से 9567 अंक और सर्टिफिकेशन के

लिए निर्धारित 2500 अंकों में से पूरे अंक प्राप्त किए। इस प्रकार 12 हजार 500 अंकों में से भोपाल शहर ने 12 हजार 067 अंक अर्जित करते हुए 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में दूसरा और प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

पिछली बार पांचवें नंबर पर था भोपाल

पिछले सर्वे में भोपाल 5वें नंबर पर था। कचरे की प्रोसेसिंग में सुधार और डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन की व्यवस्था को और पुख्ता कर भोपाल ने दावा मजबूत किया है। वहीं, फरवरी में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) की वजह से भी भोपाल को फायदा मिलेगा।

स्वच्छ सर्वेक्षण में भोपाल का अब तक का सफर

■ स्वच्छ सर्वेक्षण में भोपाल ने 2017 और 2018 में लगातार दो साल देश में दूसरी रैंक हासिल की थी।

■ 2019 में भोपाल खिसककर 19वें नंबर पर आ गया। उस समय अफसरों के लगातार तबादले के कारण तैयारियों की दिशा ही तय नहीं हो पाई थी।

■ 2020 में कम बैक करते हुए 12 पायदान ऊपर खिसका और 7वीं रैंक हासिल की।

■ 2021 के सर्वेक्षण में भी भोपाल ने 7वां स्थान हासिल किया था।

■ 2022 के सर्वेक्षण में भोपाल की रैंक सुधरी और यह छठवें स्थान पर आ गया। वहीं, भोपाल को 5 स्टार मिले थे।

■ 2023 के सर्वेक्षण में पांचवीं रैंकिंग रही थी।

■ इस बार भोपाल से 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में दूसरा स्थान हासिल किया।

पत्रकार बनने का सुनहरा अवसर

अगर आपके अंदर लिखने का कौशल है और पत्रकारिता में रुचि है, तो 'न्यूज क्राइम फाइल' को आपकी तलाश है। 'न्यूज क्राइम फाइल' से जुड़ कर आप हर माह दस हजार रुपये तक कमा सकते हैं। 'न्यूज क्राइम फाइल' भोपाल, ग्वालियर, सतना, सागर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, मंदसौर और नीमच में ब्यूरो ऑफिस खोलने जा रहा है। इच्छुक उम्मीदवार तत्काल हमें अपना बायोडाटा मेल करें या व्हाट्सअप करें।

उदय प्रताप सिंह चौहान (संपादक) 07223003441

website: www.newscrimfile.com

email:



मंदसौर में भाजपा नेता की हत्या

घर की दूसरी मंजिल पर सोए थे, सुबह खून से लथपथ शव मिला; बाँड़ी पर धारदार हथियार के निशान



श्यामलाल धाकड़

न्यूज क्राइम फाइल

मंदसौर के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के हिंगोरिया बड़ा में भाजपा मंडल उपाध्यक्ष श्यामलाल धाकड़ (45) की गुरुवार रात धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। श्यामलाल अपने घर की दूसरी

मंजिल पर सो रहे थे। किसी अज्ञात व्यक्ति ने उन पर हमला किया। शुक्रवार सुबह परिजन को श्यामलाल का खून से लथपथ शव मिला। घटना के वक्त परिजन घर के नीचे वाले हिस्से में थे। एसपी अभिषेक आनंद ने बताया, पुलिस और स्नस्सटीम मौके पर पहुंची। इन्वेस्टिगेशन के बाद

शव को पीएम के लिए पहुंचाया। अब तक जो तथ्य सामने आए हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि किसी हथियार से उन पर वार किया गया है। बाँड़ी पर मल्टीपल चोट के निशान मिले हैं, जिससे उनकी मौत हुई है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद मौत के कारणों की पुष्टि होगी। फिलहाल

परिवारजनों से चर्चा की जा रही है। हत्या की आशंका और टेक्निकल एविडेंस के तौर पर आगे की कार्रवाई करेंगे।

2021 से मंडल उपाध्यक्ष थे धाकड़

स्थानीय लोगों ने बताया कि श्यामलाल धाकड़ साल 2021 से लगातार भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता और मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बूढ़ा मंडल से उपाध्यक्ष थे। वे पार्टी के हर कार्यक्रम में बढ़चढ़ कर हिस्सा लेते थे। उनका एक बेटा और एक बेटी है।

टीआई बोले- हमलावर की तलाश कर रहे हैं

थाना प्रभारी प्रभात सिंह गौड़ ने बताया- मर्ग कायम कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। परिजन से पूछताछ के साथ आसपास के क्षेत्रों में तलाशी अभियान जारी है।

डिप्टी सीएम देवड़ा ने जांच के आदेश दिए

डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा- पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता श्यामलाल धाकड़ का शव उनके ही घर में मिलने का समाचार प्राप्त हुआ। मैंने जिला पुलिस अधिकारियों से चर्चा कर निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने हत्या की आशंका जाहिर की है। घटनाक्रम का जल्द से जल्द खुलासा कर जो भी आरोपी हों, उन्हें जेल की सींखचों में पहुंचाएं।

सौजन्य भेंट



राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल का शुक्रवार को राजभवन में उप-मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने पुष्प-गुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया।

मोबाइल चोरी के आरोपी से 9 और फोन बरामद



न्यूज क्राइम फाइल

खरगोन के जवाहर नगर क्षेत्र में मोबाइल शॉप से चोरी के मामले में रिमांड में आरोपी उमेश उर्फ फटफटी यादव से 2.22 लाख रुपए के 9 और मोबाइल बरामद किए गए हैं। इससे पहले गुरुवार को पुलिस ने आरोपी को 14.36 लाख रुपए मूल्य के 62 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया था। अब तक कुल 16.59 लाख रुपए के 71 मोबाइल बरामद हो चुके हैं। वीवो मोबाइल कंपनी के फ्रेंचाइजी आशीष ऐरन की दुकान में 10 जुलाई की रात चोरी हुई थी। चोर ने दुकान का ताला तोड़कर अलमारियों में रखे वीवो कंपनी के मोबाइल, रिपेयर के फोन, पेन ड्राइव और चार्जर सहित कई एसेसरीज चुराए थे। एसपी धर्मराज मीणा के मुताबिक, क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद पुलिस आरोपी तक पहुंची। कोतवाली थाना प्रभारी बीएल मंडलोई ने बताया कि आरोपी का अपराधिक रिकॉर्ड है। उस पर भीकनगांव थाने में 5, मेनगांव और गोगावा थाने में एक-एक केस दर्ज है।



अतिथि शिक्षक नहीं लगा रहे मोबाइल ऐप से अटेंडेंस

स्कूल शिक्षा विभाग ने कहा-
मानदेय नहीं मिलेगा; अतिथि
शिक्षक संघ की अवकाश
देने की मांग

न्यूज़ क्राइम फाइल

मध्यप्रदेश में शिक्षक और अतिथि शिक्षक गेस्ट टीचर्स की ई-अटेंडेंस व्यवस्था जुलाई के पहले 15 दिन में पूरी तरह फेल हो गई है। इसी को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने अब सख्त कदम उठाया है। विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 18 जुलाई से जो गेस्ट टीचर ई-अटेंडेंस ऐप से अटेंडेंस नहीं लगाएंगे, उन्हें गैरहाजिर माना जाएगा और मानदेय (वेतन) नहीं दिया जाएगा। विभाग ने सभी जिलों के गेस्ट टीचर्स की ई-अटेंडेंस की रिपोर्ट भी जारी की है और निर्देश दिया है कि इस पर सख्ती से अमल कराया जाए। हालांकि अतिथि शिक्षक संघ का कहना है कि जब तक अवकाश की सुविधा नहीं मिलेगी, तब तक ई-अटेंडेंस नहीं लगाएंगे। अतिथि शिक्षकों की इस चेतावनी के बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने सख्त लहजे में कहा है कि यह व्यवस्था 18 जुलाई से प्रदेश में अनिवार्य रूप से लागू होगी। जिन अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति शिक्षक एप के माध्यम से दर्ज नहीं होगी उनका मानदेय का भुगतान नहीं किया जा सकेगा।

हमारे शिक्षक ऐप से अनिवार्य की गई उपस्थिति

स्कूल शिक्षा विभाग ने इस शैक्षणिक सत्र से गेस्ट टीचर्स की अटेंडेंस मोबाइल ऐप हमारे शिक्षक के जरिए दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब शिक्षक की उपस्थिति सिर्फ ऐप के माध्यम से ही मान्य मानी जाएगी। हालांकि, अभी तक



कई गेस्ट टीचर्स इस आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। इस पर लोक शिक्षण आयुक्त ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि लगभग 80 लाख अतिथि शिक्षकों ने ई-अटेंडेंस दर्ज नहीं की है, जो कि बहुत ही निराशाजनक है।

ई-अटेंडेंस नहीं लगाई तो रुकेगा मानदेय

विभाग ने साफ कहा है कि सभी गेस्ट टीचर्स को सूचना दी जाए कि अगर वे हमारे शिक्षक ऐप से अटेंडेंस दर्ज नहीं करते हैं, तो उन्हें गैरहाजिर माना जाएगा और उनका मानदेय नहीं मिलेगा। यह ई-अटेंडेंस की व्यवस्था 1 जुलाई 2025 से शुरू की गई है। लेकिन पहले 15 दिन की समीक्षा में सामने आया कि 80% से ज्यादा गेस्ट टीचर्स ने ऐप से अटेंडेंस नहीं लगाई है।

सिर्फ डिंडोरी में 50 प्रतिशत से ज्यादा अटेंडेंस

शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश के 55 जिलों में से केवल डिंडोरी ऐसा जिला है जहां 57% गेस्ट टीचर्स ने ई-अटेंडेंस दर्ज की है। इसके बाद झाबुआ में 48%, खरगोन में 45%, नरसिंहपुर और शहडोल में 44-44% उपस्थिति दर्ज की गई। वहीं, अनूपपुर सबसे पिछड़ा जिला रहा, जहां 17 गेस्ट टीचर्स में से किसी ने भी एक भी दिन अटेंडेंस नहीं लगाई। इसके

अलावा निवाड़ी और अलीराजपुर में 7-7%, मऊगंज और हरदा में 8-8% अटेंडेंस दर्ज की गई।

जब तक अवकाश की सुविधा नहीं मिलेगी, नहीं लगाएंगे ई-अटेंडेंस

अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष सुनील परिहार ने स्कूल शिक्षा विभाग की ई-अटेंडेंस अनिवार्यता पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि पिछले 17 सालों में अतिथि शिक्षकों को एक भी अवकाश की सुविधा नहीं दी गई है, जबकि अतिथि विद्वानों को यह सुविधा उपलब्ध है। परिहार ने कहा, हमारे पास न तो दुर्घटना बीमा है और न ही महिला शिक्षकों को प्रसूति अवकाश मिलता है। कई अतिथि शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें मात्र 10,000 मानदेय मिलता है और वे पिछले चार महीनों से बेरोजगार हैं। कई के पास स्मार्टफोन तक नहीं हैं, ऐसे में वे ई-अटेंडेंस कैसे लगाएं? सुनील परिहार ने बताया कि इस फरमान के विरोध में गुरुवार को प्रदेश के सभी जिलों में ज्ञापन सौंपा जाएगा। संगठन की मांग है कि जब तक अतिथि शिक्षकों को सम्मानजनक सुविधाएं नहीं दी जाती, तब तक उन्हें तकनीकी व्यवस्थाओं के लिए बाध्य न किया जाए।

सिंघार बोले-पर्यावरण अनुमतियों में 3 हजार करोड़ की वसूली हुई

न्यूज़ क्राइम फाइल

स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट एसेसमेंट अथॉरिटी (सिया) के चेयरमैन शिवनारायण सिंह चौहान और पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव नवनीत मोहन कोठारी के बीच चल रहे विवाद पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की एंट्री हुई है। सिंघार ने भोपाल में अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये आरोप लगाया कि पर्यावरण विभाग की अनुमतियां देने में 3 करोड़ से लेकर 5 करोड़ रुपए तक उद्योगपतियों से वसूले। करीब दो से तीन हजार करोड़ रुपए जो वसूले गए वो कहां गए?

नेता प्रतिपक्ष ने कहा-

अभी सिया(स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट एसेसमेंट अथॉरिटी) में 400 कंपनियों को सिया की अनुमति दी गई। इसका क्या कारण था? चीफ सेक्रेटरी ने मीटिंग क्यों नहीं बुलाई? नवनीत मोहन कोठारी ने परमिशन क्यों दीं? श्रीमान शुक्ला ने प्रमुख सचिव कोठारी के कहने पर क्यों परमिशन दी गई। मेरी मांग है कि नवनीत कोठारी और श्रीमान शुक्ला के कार्यकाल की जांच होनी चाहिए।

अब जानिए क्या है ये पूरा विवाद

खनिज के 200 समेत 450 केस में पर्यावरणीय मंजूरी दिए जाने के मामले में स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट एसेसमेंट अथॉरिटी (सिया) के अध्यक्ष शिव नारायण सिंह चौहान ने मुख्य सचिव अनुराग जैन को पत्र लिखकर पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव नवनीत मोहन कोठारी और एफको की एजीक्यूटिव डायरेक्टर आर उमा महेश्वरी पर गैर कानूनी काम करने का आरोप लगाया था। चौहान



ने दोनों अफसरों पर आपराधिक केस दर्ज करने और तत्काल निर्लंबित करने की सिफारिश की थी। 9 जुलाई को लिखे पत्र में चौहान ने कहा कि पीएस और एफको डायरेक्टर ने 700 से अधिक लंबित प्रकरणों में से 237 पर्यावरणीय मंजूरीयां गैर कानूनी तरीके से पिक एंड चूज पैटर्न पर जारी कर दी है। जबकि सिंहस्थ से जुड़े कई अहम प्रोजेक्ट को लटकाकर रखा है। दोनों आईएस अधिकारी पिछले दो माह से जानबूझकर सिया की बैठकें नहीं होने दे रहे हैं।

एक करोड़ की रिश्त मांगी, 53 लाख में सौदा हुआ, 44 लाख ले चुके थे

एमपी का घूसखोर नारकोटिक्स इंस्पेक्टर और दलाल गिरफ्तार



महेंद्र सिंह
नारकोटिक्स इंस्पेक्टर

जगदीश मेनारिया
दलाल

न्यूज़ क्राइम फाइल

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जयपुर टीम ने मध्यप्रदेश के केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के घूसखोर

इंस्पेक्टर और दलाल को पकड़ा। इंस्पेक्टर ने नारकोटिक्स के केस में परिवार को नहीं फंसाने की एवज में 1 करोड़ रुपए की रिश्त की मांगी थी। सौदा 53 लाख रुपए में तय हुआ था। 3 किशत में दलाल के जरिए 44 लाख ले चुका था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जयपुर में 15 जुलाई को परिवारी बड़ीसादड़ी निवासी मांगीलाल गुर्जर ने शिकायत दी थी। मांगीलाल ने बताया था कि उज्जैन में तैनात नारकोटिक्स इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह ने बड़ीसादड़ी स्थित उसके घर पर 27 मार्च को छपा मारकर 400 किलो डोडाचूरा जब्त किया था। छापे के बाद, महेंद्र सिंह ने मांगीलाल के परिवार से कहा था कि वे चित्तौड़गढ़ के डूंगला में आला खेड़ी निवासी जगदीश मेनारिया से संपर्क कर लें। थोड़े दिन बाद जगदीश ने खुद मांगीलाल से संपर्क किया।

महेंद्र सिंह ने जगदीश के जरिए मांगीलाल को धमकी दी कि अगर वह 1 करोड़ रुपए की रिश्त नहीं देगा, तो उसे और उसके पूरे परिवार को नारकोटिक्स के केस में फंसा देगा। उसके बाद सौदा 53 लाख में तय हो गया। मांगीलाल तीन किशत में दलाल के जरिए 44 लाख रुपए आरोपी को दे चुका था, लेकिन रिश्त का सिलसिला यहीं नहीं रुका।

महेंद्र सिंह और जगदीश मेनारिया ने नौ लाख रुपए की और मांग की। परेशान होकर मांगीलाल ने सीबीआई जयपुर की टीम को शिकायत की। सीबीआई टीम ने शिकायत का सत्यापन करवाया, तो सही निकली। इसके बाद सीबीआई की टीम की योजना के अनुसार पीड़ित ने तीन लाख रुपए देने के बहाने गुरुवार रात दलाल को सांवलिया जी के पास एक होटल में बुलवाया। जैसे ही दलाल पैसे लेने आया, सीबीआई की टीम ने उसे पकड़ लिया।

महेंद्र सिंह को उज्जैन से गिरफ्तार किया

दलाल की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ की गई, तो पूरे मामले में नारकोटिक्स इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह का नाम आया। इसके बाद सीबीआई की टीम ने शुक्रवार को महेंद्र सिंह को उज्जैन से गिरफ्तार किया। जांच में यह भी पता चला कि आरोपी महेंद्र सिंह ने सीकर, जयपुर और नीमच में गलत तरीके से कमाए गए पैसे से कई संपत्तियां खरीदी हैं।

एयरपोर्ट पर घास काटने के लिए 93 लाख का टेंडर

700 एकड़ ऑपरेशनल क्षेत्र में जानवरों से बचाव के लिए कटेगी घास, पहले मशीन से होता था काम

न्यूज़ क्राइम फाइल

देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदौर पर बारिश के मौसम में ऑपरेशनल एरिया में उगने वाली घास की कटाई के लिए इस बार एयरपोर्ट प्रबंधन 93 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करने जा रहा है। इसके लिए बाकायदा टेंडर जारी किया गया है। यह राशि एक साल तक घास काटने के लिए अकुशल श्रमिकों की आपूर्ति पर खर्च होगी। प्रबंधन ने मैनपावर सप्लायर कंपनियों को आमंत्रित किया है जो रोजाना लगभग 20 श्रमिक उपलब्ध करवाएंगी। इस टेंडर की अनुमानित लागत 93.32 लाख रुपए है, जबकि पिछले वर्ष इसी कार्य के लिए 70 लाख का टेंडर निकाला गया था। यह टेंडर 4 अगस्त को खोला जाएगा और न्यूनतम दर पर पात्र कंपनी को ठेका दिया जाएगा।

पहले मशीन से होती थी कटाई, अब हर साल लाखों खर्च



पूर्व में एयरपोर्ट डायरेक्टर रही अर्यमा सान्याल ने एक आधुनिक घास काटने की मशीन मंगवाई थी, जो तेजी से घास काटकर उसके गट्टर बना देती थी। करीब 700 एकड़ के क्षेत्र में फैली घास को एक माह में साफ कर दिया जाता था। यह घास लगभग 1800 टन होती थी, जिसे नगर निगम के माध्यम से चिड़ियाघर में शाकाहारी जानवरों के लिए भेजा जाता था। अब मशीन के उपयोग की बजाय हर

साल नए सिरे से श्रमिकों पर लाखों खर्च किए जा रहे हैं, जिससे न केवल लागत बढ़ी है बल्कि जानवरों तक घास पहुंचना भी बंद हो गया है।

घास से उड़ानों को खतरा, जानवरों के प्रवेश की आशंका

700 एकड़ के खुले ऑपरेशनल क्षेत्र में बारिश के दौरान तेजी से घास उगती है। इससे छोटे जानवरों के छिपने का खतरा रहता है, जो रनवे पर आ सकते हैं। कुछ साल पहले एक

सियार विमान के पहिए से टकरा गया था। ऐसे हादसों से बचाव के लिए नियमित रूप से घास कटाई जरूरी है।

एयर इंडिया एक्सप्रेस ने इंदौर-बेंगलुरु फ्लाइट की सेवाएं की रह

शुक्रवार सुबह एयर इंडिया एक्सप्रेस की इंदौर-बेंगलुरु फ्लाइट को निरस्त कर दिया गया, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हुई। यह उड़ान सुबह 9:20 बजे इंदौर पहुंचकर 9:50 बजे वापस बेंगलुरु जाती है, लेकिन एयरलाइन ने ऑपरेशनल कारणों का हवाला देते हुए सेवा निरस्त कर दी। हालांकि एयरलाइन का दावा है कि यात्रियों को पहले ही सूचना दी गई थी, लेकिन कई यात्री जानकारी के अभाव में एयरपोर्ट पहुंचे और फ्लाइट रद्द होने पर नाराज होकर हंगामा भी किया। गुरुवार रात एलायंस एयर की दिल्ली से इंदौर आने वाली फ्लाइट निर्धारित समय 7:40 बजे के बजाय 10:30 बजे पहुंची। तकनीकी खराबी के चलते यह देरी हुई।

गैंगस्टर जुबेर का जुलूस निकालने वाले पुलिसकर्मियों पर होगी कार्रवाई

जबलपुर हाईकोर्ट का मानवाधिकार आयोग को जांच का आदेश; दाढ़ी-मूंछ मुंडवाकर भोपाल में घुमाया था

न्यूज क्राइम फाइल

भोपाल पुलिस के कुख्यात गैंगस्टर जुबेर मौलाना का सिर और दाढ़ी-मूंछ मुंडवाकर जुलूस निकालने के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश मानवाधिकार आयोग को कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। जुबेर की पत्नी शमीम बानो ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि इस्लाम में दी गई व्यवस्था के खिलाफ पुलिस ने यह कदम उठाया। जुबेर और उसके तीन गुर्गों को दो माह पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके पास से एक देसी पिस्टल, चार जिंदा कारतूस और तीन छुरी जब्त की गई थीं। जुबेर और उसके साथियों ने शहर के मंगलवारा और टीला जमालपुरा क्षेत्र में वाहनों में तोड़-फोड़ करने के साथ ही फायरिंग की थी। हालांकि पुलिस का दावा था कि जुबेर ने अपनी पहचान छिपाने के लिए खुद ही दाढ़ी, मूंछ और सिर मुंडवा लिया था।

भोपाल कमिश्नर और आयोग को



लिखा था पत्र

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रशांत चौरसिया ने कोर्ट को बताया कि वारंट तामीली के मामले में भोपाल पुलिस ने जुबेर को

गिरफ्तार किया था। फिर उसका जुलूस निकाला गया। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि भोपाल कमिश्नर और मानव अधिकार आयोग को शिकायत पत्र देकर दोषी पुलिस कर्मचारियों

की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की गई थी।

गिरफ्तारी के बाद जुलूस नहीं निकाल सकते

अधिवक्ता प्रशांत चौरसिया ने बताया कि यह मामला आर्टिकल 21, 22, 25 और ह्यमन राइट्स के उल्लंघन का है। कोर्ट को बताया गया कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद उसका जुलूस नहीं निकाला जा सकता है। पुलिस को संबंधित कोर्ट में पेश करने का अधिकार है, इसके बाद उसे ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा।

जुबेर पर भोपाल में कई केस दर्ज

गैंगस्टर जुबेर ने पुरानी रंजिश के चलते भोपाल में बदमाश साद खान पर फायरिंग की थी। आरोपियों के गोली चलाते हुए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए थे। जुबेर मौलाना के खिलाफ गैरतगंज के अलावा भोपाल में कई अपराध दर्ज हैं। उस पर 30 हजार रुपए का इनाम भी घोषित था।

रतलाम में लाठीचार्ज के विरोध में करणी सेना का प्रदर्शन



न्यूज क्राइम फाइल

रतलाम में 13 जुलाई को सेजावता फोरलेन पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में करणी सेना शुक्रवार को प्रदर्शन कर रही है। सेना के सदस्यों ने दोपहर में नेहरू स्टेडियम में एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। इस दौरान एडीएम डॉ. शालिनी श्रीवास्तव को ज्ञापन देकर एसपी राकेश खाखा को हटाने की मांग की गई।

ड्रोन से निगरानी कर रही पुलिस

इससे पहले दोपहर करीब 12 बजे से मौके पर करणी सेना के कार्यकर्ता जमा होने लगे। इस दौरान डीएसपी अजय सारवान समेत शहर के चारों थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौजूद हैं। पुलिस ड्रोन से भी निगरानी कर रही

है। एसपी के खिलाफ कलेक्टर को बात हरदा कांड की जांच को लेकर सीएम के नाम अलग-अलग दो ज्ञापन सौंपे गए।

एसपी खाखा पर बेवजह लाठीचार्ज करवाने का आरोप

करणी सेना के यादवेंद्रसिंह ने आरोप लगाया कि एसपी खाखा ने बिना कारण कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों पर लाठीचार्ज किया और गालियां दीं। रविवार को हरदा में हुए लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन के बाद, एसडीओपी किशोर पाटनवाला और थाना प्रभारी गायत्री सोनी की समझाइश पर धरना समाप्त कर दिया गया था। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जब वे पास की चाय की दुकान पर चर्चा कर रहे थे, तब एसपी ने बिना किसी कारण लाठीचार्ज कर दिया।

भोपाल में पब्लिक टॉयलेट्स में जाना महंगा पड़ेगा

6 की जगह 10 रुपए लगेंगे; कांग्रेस का विरोध, कहा- इससे तो खाना सस्ता है



न्यूज क्राइम फाइल

भोपाल के पब्लिक टॉयलेट्स में जाना महंगा पड़ेगा। मेयर इन कौंसिल (एमआईसी) में प्रस्ताव पास होने के बाद कांग्रेस खुलकर मैदान में उतर गई है। शुक्रवार को कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। पार्षद योगेंद्र सिंह गुड्डू चौहान ने कहा कि दीनदयाल रसोई में 5 रुपए में खाना मिल रहा है। दूसरी ओर, टॉयलेट्स के रेट बढ़ाए जा रहे हैं। पिछले दिनों एमआईसी की बैठक हुई थी। इसमें सुलभ इंटरनेशनल ने 25 स्थानों पर संचालित सार्वजनिक शौचालय में उपयोगकर्ता शुल्क दर 6 से बढ़ाकर 10 रुपए किए जाने की मंजूरी चाही थी। एमआईसी ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया था। इसके बाद से ही कांग्रेस विरोध कर रही है। शुक्रवार को शिवाजी नगर स्थित सुलभ कॉम्प्लेक्स के सामने कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। इस मामले में एमआईसी मेंबर आरके सिंह बघेल ने बताया

कि कई साल से 6 रुपए ही शुल्क लिया जा रहा था। कई बार खुले पैसे को लेकर दिक्कतें होती थीं। लोग खुले लेकर नहीं आते थे। यह बोझ बढ़ाने वाला नहीं है और न ही विरोध जैसी बात है। एमआईसी में यह प्रस्ताव पास हो गया है।

स्वच्छता अभियान पर असर पड़ेगा

पार्षद चौहान ने कहा कि शुल्क बढ़ने से स्वच्छता अभियान पर भी असर पड़ेगा। अभी 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में भोपाल दूसरे नंबर पर आया है। शुल्क बढ़ने से अभियान पर असर पड़ सकता है। लोग पैसे नहीं देते हैं तो वे खुले में जाएंगे। शुल्क बढ़ाना जबरन बोझ बढ़ाने जैसा है।

परिषद में प्रस्ताव आएगा, विरोध करेंगे

कांग्रेसी पार्षदों ने कहा कि 24 जुलाई को नगर निगम परिषद की बैठक होगी, जिसमें यह प्रस्ताव लाया जाएगा। बैठक में इस प्रस्ताव का विरोध करेंगे।



सड़क के गड्ढों पर गरमाई राजनीति

पीसीसी चीफ बोले-सरकार को गड्ढों में डूब मरना चाहिए, मंत्री जल समाधि ले लें

न्यूज़ क्राइम फाइल

सड़कों में हो रहे गड्ढों को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। सड़कों के निर्माण में करप्शन का जिक्र करते हुए पटवारी ने कहा कि गड्ढों में सरकार को डूबकर मर जाना चाहिए। मंत्री को जल समाधि ले लेना चाहिए या फिर स्थायी समाधान ढूँढना चाहिए। पटवारी ने प्रदेश के आईएस-आईपीएस अफसरों पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि इनकी वैध और अवैध संपत्ति की जानकारी कांग्रेस जुटा रही है। पटवारी ने ये बातें गुरुवार को मीडिया से चर्चा में कीं। उन्होंने कहा कि एमपी में सड़कों की हालत सबके सामने है। लोगों का पैसा लूटने वाले मंत्री जवाबदेही स्वीकार करने के बजाय यह कह रहे हैं कि सड़कें हैं तो गड्ढे होते रहेंगे। एक भी मंत्री ऐसा नहीं है जो लूट के काम में न लगा हो।

चहेती कंपनियों को टेंडर देने के नियम

पटवारी ने कहा कि विधानसभा सत्र के पहले कांग्रेस का दो दिनी प्रशिक्षण हो रहा है, जिसमें एमपी सरकार के 52 घपलों पर चर्चा होगी और इसे विधानसभा में जोर-शोर से उठाने के बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्होंने सिंहस्थ के लिए कराए जाने वाले कामों में करप्शन का आरोप लगाते हुए कहा कि सिंहस्थ को लेकर एमपी में सरकार द्वारा ऐसे नार्म्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें चहेती कंपनियों को



सीधा टेंडर देने की प्लानिंग की जा रही है। हैदराबाद और गुजरात की कंपनियों को इसमें फायदा पहुंचाया जा रहा है।

कांग्रेस लाएगी रोजगार, करप्शन पर श्वेत पत्र

पीसीसी चीफ पटवारी ने कहा कि वर्ष 2013 से आज तक कितने बच्चों को रोजगार दिया है। इसका मामला विधानसभा में उठाएंगे।

कांग्रेस रोजगार और करप्शन को लेकर श्वेत पत्र लाएगी। सरकार से श्वेत पत्र मांग रहे हैं पर सरकार तो दे ही नहीं रही है। पटवारी ने कहा कि सरकार से यह मांग है कि इन्वेस्टर समिट का श्वेत पत्र जारी करे।

आईएस-आईपीएस की संपत्ति का ब्योरा जुटा रहे

पटवारी ने मीडिया के सामने संविधान की

किताब दिखाते हुए कहा कि संविधान की शपथ लेने वाले आईएस-आईपीएस अफसरों की वैध और अवैध संपत्ति की जानकारी जुटा रहे हैं। किस आईएस-आईपीएस की कितनी संपत्ति कहां-कहां है। इसका ब्योरा मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि आईएस-आईपीएस अफसर बीजेपी का कार्यकर्ता बनकर घूम रहे हैं।

कलेक्टरों की भाषा शैली अच्छे जनसेवक की नहीं

पटवारी ने कहा कि कलेक्टरों की भाषा शैली अच्छे जनसेवक की नहीं बची है। कलेक्टर किसी को चांटा मार रहा है, किसी को औकात बता रहा है। अशोकनगर कलेक्टर और एसपी के विरुद्ध भी सभी विधायक बात करेंगे। यहां हुई एफआईआर के मामले में पारदर्शिता नहीं रही है।

बीजेपी पदाधिकारियों को भी घेरा

पटवारी ने कहा कि बीजेपी के चार बार के मंडल अध्यक्ष, पार्षदों की आर्थिक स्थिति का पता लगा लो। बड़े नेताओं की संपत्ति का ब्योरा लेने की व्यवस्था बन जाए तो 80 फीसदी लोग जेल चले जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि विधायकों के प्रशिक्षण में बीजेपी सरकार के 52 घपलों पर डिस्कशन कर उसे जनता तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सरकार में बच्चों को समय पर छत्रवृत्ति नहीं मिलती है। आदिवासियों की एक लाख हेक्टेयर जमीन गैर आदिवासियों को बेची गई। नल से जल नहीं नल से भ्रष्टाचार हो रहा है। स्मार्ट मीटर वसूली का जरिया बन गया है।

आबकारी अफसर ने शराब दुकान कर्मचारियों को लात-घूंसे मारे

न्यूज़ क्राइम फाइल

जबलपुर में सहायक आबकारी आयुक्त संजीव दुबे ने 4 शराब दुकानों में घुसकर कर्मचारियों से मारपीट की। आरोप है कि संजीव दुबे अवैध वसूली के लिए दबाव बना रहे थे। मांग पूरी न होने पर उन्होंने लात-घूंसे मारे। कहा- मालिक से कहना दुकान सरेंडर कर दे, वरना बर्बाद कर दूंगा। पिटाई के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। जहां संजीव दुबे ने मारपीट की, वो चारों शराब दुकान ठेकेदार अजय सिंह बघेल की हैं। गुरुवार शाम को ठेकेदार नरसिंहपुर में थे। जानकारी के अनुसार, शाम को संजीव दुबे कुछ कर्मचारियों के साथ ठेकेदार की दुकानों पर गए। यहां करीब तीन घंटे तक हंगामा किया। एक दुकान में लगे सीसीटीवी की डीवीआर भी निकालकर ले गए। ठेकेदार अजय सिंह बघेल ने बताया कि मामले की शिकायत सीएम डॉ. मोहन यादव, आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा और वाणिज्यिक विभाग प्रमुख सचिव तक पहुंचाई गई है। सहायक आबकारी आयुक्त संजीव दुबे लंबे समय से छोटे ठेकेदारों को परेशान कर रहे हैं। पिटाई से घबराकर चारों दुकानों के सेल्समैन काम छोड़कर चले गए, जिससे बिक्री भी प्रभावित हो रही है। दुकानें सरेंडर करने की नौबत आ गई है।

दुकान के बाहर भी की मारपीट

जागृति इंटरप्राइजेज के पार्टनर अजय सिंह बघेल ने प्रमुख सचिव को पत्र में बताया कि वह साल 2025-26 के लिए बरेला मदिरा समूह के लाइसेंस है। 17 जुलाई को सहायक आबकारी आयुक्त बरेला शराब दुकान पहुंचे और गद्दीदार उपेंद्र मिश्रा से मालिक के बारे में पूछा। जब वह चुप रहा तो संजीव दुबे को यह बात नागवार गुजरी। उन्होंने गद्दीदार को लात-घूंसे मारे। दुकान के बाहर भी कर्मचारियों से पिटाई की। देर रात बरेला थाने में संजीव दुबे और उनके साथ आए अन्य कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई।



दुकान सरेंडर करो, वरना तबाह कर देंगे

प्रमुख सचिव को लिखे पत्र में यह भी कहा गया कि संजीव दुबे ने धमकी दी कि जिले में अब शराब दुकान नहीं चलाने देंगे। सभी लोगों पर 34(2) का प्रकरण (अवैध शराब के कब्जे और वितरण) बनाकर जेल भिजवा दूंगा। इसके बाद वह धनपुरी दुकान पहुंचे, वहां भी सेल्समैन अमर गुप्ता के साथ मारपीट की और सीसीटीवी डीवीआर अपने साथ ले गए। वहां भी यही धमकी दी गई कि दुकान सरेंडर कर दो, वरना तबाह कर देंगे। बरेला नंबर 2 और पड़वार दुकान में भी कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज की गई।

कर्मचारी चले गए, दुकान चलाना मुश्किल

ठेकेदार अजय सिंह बघेल ने पत्र में बताया कि उनके समूह की दुकानों की लाइसेंस फीस समय पर भरी जा रही है, लेकिन सहायक आबकारी आयुक्त लगातार परेशान कर रहे हैं। कर्मचारी काम छोड़कर चले गए हैं। दुकान चलाना मुश्किल हो गया है। अगर कर्मचारी नहीं लौटते, तो लाइसेंस फीस समय पर नहीं भर पाएंगे और लाइसेंस निरस्त हो सकता है। ऐसी स्थिति में इसकी पूरी जिम्मेदारी संजीव दुबे की होगी। न्यायालय की शरण लेनी पड़ सकती है।

आबकारी आयुक्त बोले- विभाग का लेना-देना नहीं

मामले पर आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल ने कहा, मेरी जानकारी में यह नहीं है कि संजीव दुबे ने मारपीट की है। अगर ऐसा हुआ है तो पुलिस अपनी जांच करेगी। ठेकेदार स्वतंत्र हैं कि थाने में शिकायत दर्ज कराएं। उसके बाद कार्रवाई संबंधित थाना पुलिस करेगी। विभाग का ऐसे विवादों से कोई लेना-देना नहीं है।

ऑफिस के बाहर लगाया पोस्टर

सहायक आबकारी आयुक्त संजीव दुबे ने अपने कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया है, जिसमें लिखा है, समस्त मीडिया से अनुरोध है कि आबकारी विभाग से संबंधित सभी जानकारी और खबरों के लिए सहायक जिला आबकारी अधिकारी दृगचंद चतुर्वेदी से संपर्क किया जाए।

42 देशों में जाने के लिए जरूरी वैक्सीनेशन बंद

एमपी के लोगों को बिजनेस, टूरिज्म वीजा नहीं मिल रहा

न्यूज क्राइम फाइल

मध्यप्रदेश के सैकड़ों लोगों की विदेश यात्रा की तैयारी पर ब्रेक लग गया है। उन्हें अब एजुकेशन, बिजनेस और टूरिज्म वीजा मिलने में परेशानी हो रही है। दरअसल, 42 देशों की यात्रा के लिए जरूरी वैक्सीनेशन एम्स भोपाल में बंद हो गया है और वीजा के लिए इसका सर्टिफिकेट जरूरी होता है। यह वैक्सीनेशन यलो फीवर के लिए होता है। अफ्रीका और लैटिसन अमेरिका के कई हिस्सों में यलो फीवर की बيمारी पाई जाती है। ऐसे में यहां यात्रा के लिए वैक्सीनेशन जरूरी होता है। एम्स भोपाल प्रदेश का एकमात्र यलो फीवर वैक्सीनेशन सेंटर है, जहां हर महीने करीब 200 से 250 लोग वैक्सीन लगवाने आते हैं। हालांकि अब एम्स भोपाल में यलो फीवर वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है, जिसके चलते वैक्सीनेशन अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है और अगली खेप कब आएगी, यह फिलहाल स्पष्ट नहीं है।

वैक्सीन सप्लाई में आई रुकावट

डॉक्टरों के मुताबिक, कोविड-19 महामारी ने यलो फीवर वैक्सीन के उत्पादन और आपूर्ति को भी प्रभावित किया है। विशेषज्ञों के अनुसार यह वैक्सीन ब्राजील, फ्रांस और रूस में बनती है और वहां से विश्व स्वास्थ्य संगठन के जरिए भारत सरकार को दी जाती है। इसके बाद वैक्सीन की खेप हिमाचल प्रदेश के कसौली स्थित केंद्रीय अनुसंधान संस्थान (सीआरआई) भेजी जाती है, जहां गुणवत्ता जांच के बाद देशभर के सेंटर्स में आपूर्ति की जाती है।

देश में 63 सेंटर, मध्यप्रदेश में सिर्फ एक

भारत में यलो फीवर टीकाकरण के लिए कुल 63 अधिकृत केंद्र हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में केवल एम्स भोपाल ही यह सुविधा देता है। अब जब यहां वैक्सीन खत्म हो गई है, तो यात्रियों को देश के अन्य राज्यों के सेंटर्स का रुख करना पड़ेगा, जिससे समय और खर्च दोनों बढ़ेंगे।

एम्स भोपाल ने कहा- नई खेप आने पर सूचना देंगे

एम्स भोपाल के यलो फीवर वैक्सीनेशन सेंटर के नोडल अधिकारी डॉ. सूर्य बाली के मुताबिक, हमारे पास वर्तमान में वैक्सीन का कोई स्टॉक नहीं है। हर बुधवार को लगने वाले टीकाकरण सत्र कैंसिल कर दिए गए हैं। जब नई खेप आएगी, तभी टीकाकरण दोबारा शुरू किया जा सकेगा। एम्स ने अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया पर पब्लिक नोटिस जारी किया है और लोगों से अपील की है कि वे टीका लगवाने के लिए यहां न आए और देश के किसी अन्य अधिकृत सेंटर में ऑप्शनल व्यवस्था करें। नई खेप आने पर इसकी सूचना अलग से दी जाएगी।

यात्रियों की बढ़ी परेशानी

एम्स भोपाल में वैक्सीन खत्म होने से वे लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, जो विदेश यात्रा की अंतिम तैयारी में थे। कई एजुकेशन, बिजनेस और टूरिज्म वीजा के आवेदन इस प्रमाणपत्र के बिना अधूरे रह जाएंगे। यात्रियों का कहना है कि उन्हें पहले से जानकारी होती तो दूसरे राज्यों में समय रहते स्लॉट बुक कर सकते थे।

क्या कर सकते हैं अब यात्री

फिलहाल यात्रियों के पास विकल्प यही है कि वे देश के किसी अन्य 63 अधिकृत सेंटर में स्लॉट बुक करें। हालांकि वहां भी वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर स्थिति साफ नहीं है। ऐसे में विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए यह एक बड़ी समस्या पैदा कर सकता है।



टीकाकरण के बाद क्या करें?

टीका लगवाने के बाद कम से कम 30 मिनट तक वैक्सीनेशन सेंटर में रुकें। किसी भी तरह की घबराहट, एलर्जी, रैश, सांस लेने में परेशानी या चक्कर आने पर तुरंत ड्यूटी डॉक्टर को सूचित करें।

यलो फीवर वैक्सीन से साइड इफेक्ट्स भी हो सकते

- हल्के दुष्प्रभाव (1 में से 4 लोगों में)
 - बुखार, शरीर में दर्द, सिरदर्द, थकान, इंजेक्शन वाली जगह पर सूजन या दर्द।
 - आमतौर पर ये असर 3-9 दिन में शुरू होते हैं और एक हफ्ते तक रहते हैं।
- गंभीर दुष्प्रभाव
 - 55 हजार में से एक में गंभीर एलर्जिक रिएक्शन।
 - 1 लाख 25 हजार में से एक में नर्वस सिस्टम पर असर।
 - 2 लाख 50 हजार में से एक में अंगों में फेल्योर वाली जानलेवा बीमारी — जिसमें आधे मामलों में मौत हो जाती है।
 - 1 लाख 30 हजार में से एक को अचानक खुजली, चक्कर या अस्थमा जैसा रिएक्शन।
 - 80 लाख में से एक को ब्रेन इन्फ्लेमेशन (एन्सेफलाइटिस) हो सकता है।

सोनम-राज को फ्लैट देने वाले शिलोम को जमानत: बैग-सबूत छिपाने के मामले में आरोपी है; राजा के भाई ने कहा- आपत्ति ली फिर भी जमानत मिल गई

न्यूज क्राइम फाइल

इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी बने शिलोम जेम्स को शुक्रवार को शिलॉन्ग कोर्ट से जमानत मिल गई। करीब 15 दिन से ज्यादा समय से शिलॉन्ग जेल में बंद था। उसके साथ बिल्डिंग के मालिक लोकेन्द्र तोमर और बलवीर को भी आरोपी बनाया था। हालांकि, शिलोम को जमानत किन शर्तों पर मिली है। इसकी जानकारी नहीं लग पाई है। बता दें, इस मामले में लोकेन्द्र और बलवीर को पहले ही जमानत मिल चुकी है। इधर, राजा रघुवंशी के भाई सचिन ने कहा कि हमारे वकील ने शिलोम की जमानत पर आपत्ति ली थी। फिर भी उसे जमानत मिल गई। हम अपने वकील से चर्चा कर आपत्ति लेंगे। शिलॉन्ग पुलिस ने राजा की हत्या के बाद सोनम-राज और उसके साथियों को कमरा किराए पर देने के साथ ही सोनम का बैग छिपाने और सबूत छिपाने के

मामले में आरोपी बनाया था। उसके बताने के बाद लोकेन्द्र और बलवीर भी इसमें आरोपी बने थे। शिलॉन्ग ले जाने के बाद फिर लाए थे शिलोम जेम्स को पहले पुलिस सबूत छिपाने को लेकर अपने साथ लेकर गई थी। लेकिन, इसके बाद दूसरी बार इंदौर आकर पिस्टल और लैपटॉप सहित रुपए जब्त किए थे। शिलॉन्ग पुलिस इंदौर क्राइम ब्रांच के साथ रतलाम उसके ससुराल भी लेकर पहुंची थी। यहां उसने सोनम की ज्वेलरी छिपाई थी।



सोनम रघुवंशी

राज कुशवाहा

शिलोम जेम्स



भाजपा किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देगी, ये मोदी की गारंटी है

मोदी बंगाल में बोले- घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई होगी

संदीप कुमार सिंह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में कहा- बंगाल में टीएमसी ने अपने स्वार्थ के लिए घुसपैठ को बढ़ावा दिया। इसके लिए इकोसिस्टम बनाया जा रहा है। ये राज्य-देश और बांग्ला संस्कृति के लिए खतरा है। उन्होंने आगे कहा- टीएमसी ने घुसपैठियों के पक्ष में नई मुहिम शुरू की। मैं साफ कहता हूँ- जो भारत का नागरिक नहीं है और घुसपैठ करके आया है, उसपर संविधान के तहत कार्रवाई होकर रहेगी। बंगाल के खिलाफ साजिश को भाजपा कामयाब नहीं होने देगी, ये मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी ने दुर्गापुर में 5000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसमें ऑयल, गैस, बिजली, सड़क और रेल से जुड़ी कई अन्य विकास परियोजनाएं शामिल हैं। दुर्गापुर बंगाल के पश्चिम वर्धमान जिले का शहर है। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 2025 में मोदी की यह दूसरी पश्चिम बंगाल यात्रा है। इससे पहले उन्होंने 29 और 30 मई को अलिपुरद्वार और कूच बिहार में परियोजनाओं का शिलान्यास किया था।

मोदी के संबोधन की 6 बातें...

मुर्शिदाबाद घटना में पुलिस ने कुछ न किया: बंगाल में मुर्शिदाबाद जैसी घटना हुई है। हत्या हो जाती हो और पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। यहां राज्य सरकार जान और दुकान की रक्षा नहीं कर सकती, तो निवेशकों को भी चिंता होती है। बंगाल के अस्पताल सुरक्षित नहीं- आज बंगाल के अस्पताल भी सुरक्षित नहीं हैं, जब डॉक्टर बेटी के साथ अत्याचार हुआ तो टीएमसी सरकार अपराधी को बचाने में लगी रही। देश इससे उभरा ही नहीं तो एक और कॉलेज में बेटी के साथ दुर्व्यवहार हुआ। टीएमसी के नेता इसके आरोपियों को भी बचाने में लगे हैं।

टीएमसी सरकार बंगाल के विकास के आगे खड़ी:

टीएमसीसरकार बंगाल के विकास के आगे दीवार बनकर खड़ी है। जिस दिन TMC की दीवार गिरी, तब बंगाल विकास की गति पकड़ लेगी। टीएमसी की सरकार जाएगी, तभी असली परिवर्तन आएगा। हम बंगाल में अवसर मांग रहे हैं। बंगाल की नीति भ्रष्टाचारियों ने बनाई-

पश्चिम बंगाल की नीति भी भ्रष्टाचारियों के लिए बनाई जाती है। युवाओं की शिक्षा और कौशल के साथ जो कुछ यहां हो रहा है वह चिंता बढ़ाने वाला है। युवाओं की शिक्षा और कौशल के साथ जो कुछ यहां हो रहा है वह चिंता बढ़ाने वाला है।

बंगाल के उद्योगपतियों ने देश के इंडस्ट्रीज की नींव रखी:

पश्चिम बंगाल की धरती प्रेरणाओं से भरी पड़ी है, यह देश के पहले उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद की भूमि है। उन्होंने देश के इंडस्ट्रीज की नींव रखी। ये बिधान चंद्र राय जैसे उद्योग पति की नगरी है। इस भूमि पर सर विरेन्द्र मुखर्जी हुए, जिनके वीजन से भारत को स्टील उद्योग की नींव मिली ऐसे लोगों ने ही बंगाल को आगे बढ़ाया है।

बंगाल में सबसे ज्यादा बंदे भारत ट्रेन चल रही:

रेल कनेक्टिविटी सुधारने के लिए बहुत काम हुआ है। यह देश के उन राज्यों में से एक है जहां सबसे ज्यादा बंदे भारत ट्रेन चल रही हैं। कोलकाता मेट्रो का विस्तार हो रहा। रेलवे स्टेशनों को मॉडर्न बनाया जा रहा है। आज बंगाल को दो नए रेलवे ओवरब्रिज भी मिले हैं। BPCL सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना, लागत- 1,950 करोड़ प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के बांकुरा और पुरुलिया जिले में लगभग 1,950 करोड़ रुपये की लागत वाली भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की शहरी गैस वितरण परियोजना की आधारशिला रखी। यह परियोजना के तहत घरों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को PNG और CNG कनेक्शन मुहैया कराई जाएगी। इससे क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। दुर्गापुर-कोलकाता नेचुरल गैस पाइपलाइन, लागत - 1,190 करोड़ प्रधानमंत्री दुर्गापुर-हल्दिया नेचुरल गैस पाइपलाइन के दुर्गापुर से कोलकाता खंड (132 किलोमीटर) की शुरुआत की। इसे जगदीशपुर-हल्दिया और बोकारो-धामरा पाइपलाइन के एक हिस्से के रूप में बिछाया गया है। इस प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। 1,190 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाला दुर्गापुर से कोलकाता खंड पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान, हुगली और नादिया जिलों से होकर गुजर रहा है। दुर्गापुर स्टील और रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन में FGD सिस्टम, लागत- 1,457 करोड़ प्रधानमंत्री दुर्गापुर स्टील थर्मल पावर स्टेशन और दामोदर घाटी निगम के रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन की 1,457 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली फ्लू-गैस डिसल्फराइजेशन यूनिट भी राष्ट्र को समर्पित की। इससे वायु प्रदूषण में कमी आएगी। पुरुलिया-कोटशिला रेल लाइन का दोहरीकरण, लागत- 390 करोड़ बंगाल में रेलवे के जरिए औद्योगिक कनेक्टिविटी में सुधार को बढ़ावा देते हुए, प्रधानमंत्री मोदी पुरुलिया में 390 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 36 किलोमीटर लंबी पुरुलिया-कोटशिला रेल लाइन के दोहरीकरण प्रोजेक्ट को भी हरी झंडी दिखाई। इससे जमशेदपुर, बोकारो और धनबाद के उद्योगों का रांची और कोलकाता के साथ रेल संपर्क में सुधार होगा। माल गाड़ियों की डायरेक्ट आवाजाही होगी, जिससे समय भी बचेगा। तोपसी और पांडबेश्वर में दो रोड ओवर ब्रिज का उद्घाटन, लागत- 380 करोड़ प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम वर्धमान के तोपसी और पांडबेश्वर में सेतु भारतम कार्यक्रम के तहत बनाए 380 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बने दो रोड ओवर ब्रिज का उद्घाटन किया। इससे कनेक्टिविटी में सुधार होगा और रेलवे क्रॉसिंग पर दुर्घटनाओं को रोकने में भी मदद मिलेगी। दुर्गापुर में छह साल बाद P M मोदी की रैली बंगाल के पश्चिम वर्धमान जिले के दुर्गापुर में PM मोदी की 6 साल बाद यह दूसरी रैली है। इससे पहले वे 2 फरवरी 2019 को पहली बार दुर्गापुर गए थे।